

नई सोच का अखबार

अग्र भारत

www.agrabharat.in

दैनिक हिन्दी समाचार पत्र



वर्ष: 19 | अंक: 158 | आगरा, शनिवार 28 नवम्बर 2026 | पृष्ठ: 8 मूल्य: 2.00 रू.

एनसीआर में बढ़ी ठंड, पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा, घना कोहरा छाने का अलर्ट

आने वाले दिनों में पारा गिरेगा, दिन की गर्मी होगी कम ठंड बढ़ेगी

नई दिल्ली,(ए)। एनसीआर में सर्दी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है और पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। अब सिर्फ सुबह और शाम ही नहीं, बल्कि दिन के समय भी ठिठुरन भरी ठंड का एहसास होने लगा है। अगले दो दिनों में एनसीआर के लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा।



विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में अधिकतम पारे में भी गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे दिन की गर्मी भी कम होगी और ठंड बढ़ेगी। शहर की आबोहवा की बात करें तो फिलहाल हवा की गुणवत्ता ऑरेंज जोन में बनी हुई है यानी प्रदूषण का स्तर मध्यम से खराब श्रेणी में है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को आसमान में हल्का कोहरा रहेगा। अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 28 नवंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। तापमान में मामूली गिरावट आएगी।

विभाग के मुताबिक 30 नवंबर को महीने के आखिरी दिन कोहरा परेशान करेगा। तापमान में और गिरावट दर्ज होगी, अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 1 दिसंबर की शुरुआत भी कोहरे के साथ होगी। मध्यम कोहरा छाया रहेगा और तापमान 23 डिग्री से 9 डिग्री तक गिर सकता है। 2 दिसंबर को मौसम विभाग के मुताबिक, इस दिन हल्का कोहरा रहेगा, लेकिन ठंड बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया साइबर गुलामी सिंडिकेट का भंडाफोड़

नई दिल्ली,(ए)। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी में चल रहे अंतरराष्ट्रीय साइबर गुलामी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली-एनसीआर के कुछ कॉल सेंटरों पर छापेमारी कर पुलिस ने 164 विदेशी नागरिकों को रेस्क्यू कराया, जिन्हें बेहतर जीवन का लालच देकर भारत लाया गया था और फिर बंधक बनाकर साइबर धोखाधड़ी कराई जा रही थी। इस मामले में मलेशिया मूल के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है, जबकि दो भारतीय आरोपी फरार हैं। यह कार्रवाई एक विदेशी नागरिक द्वारा दिल्ली पुलिस को भेजे गए ईमेल के बाद शुरू हुई, जिसमें उसने अपनी आपबीती लिखी थी। संयुक्त पुलिस आयुक्त के मुताबिक बीते दिनों दिल्ली पुलिस को एक विदेशी नागरिक का ईमेल मिला था, जिसमें उसने आपबीती बताते हुए मदद मांगी थी। ईमेल में बताई गई बातों को गोपनीय तरीके से सत्यापित करने के बाद, क्राइम ब्रांच ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। छापेमारी में पुलिस ने 92 इंडोनेशियाई और 73 मलेशियाई मूल के कुल 164 विदेशी नागरिकों का रेस्क्यू किया, जिनकी उम्र करीब 19 से 25 साल के बीच थी। इन सभी ने पुलिस को अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि उन्हें बिजनेस वीजा के बहाने भारत बुलाया गया था।

बृजभूषण और योगी की एक घंटे की मुलाकात के गहरे राजनीतिक मायने

लखनऊ(ए)। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश में गुरुवार देर शाम एक बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह ने लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सवा साल बाद हुई यह बैठक एक घंटे से भी अधिक समय तक चली। राजनीतिक गलियारों में इस लंबी मुलाकात को गृह मंत्री अमित शाह की उस नसीहत से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने गिला शिकवा गोमती में बहा देने की बात कही थी, जिसने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत में गर्माहट ला दी है।



मुलाकात के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बातचीत में इसका कारण मुख्यमंत्री की माताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करना बताया। हालांकि, एक घंटे से भी अधिक समय तक चली इस लंबी बातचीत को केवल औपचारिक शिष्टाचार से कहीं बढ़कर माना जा रहा है। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब मुख्यमंत्री शुक्रवार को बृजभूषण शरण सिंह के प्रभाव वाले गोंडा, बलरामपुर और देवीपाटन का दौरा करने वाले हैं, जहां वे देवीपाटन मंदिर में रात्रि विश्राम भी करेंगे। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच बृजभूषण शरण सिंह का मुख्यमंत्री आवास पहुंचना बेहद महत्वपूर्ण है। देवीपाटन मंडल और पूर्वांचल की कई विधानसभा सीटों पर बृजभूषण शरण सिंह और उनके परिवार का सीधा राजनीतिक प्रभाव माना जाता है। चुनाव से पहले पार्टी के भीतर समन्वय साधने और क्षेत्रीय समीकरणों को अपने पक्ष में करने के लिहाज से इस लंबी बातचीत को अहम रणनीतिक कदम माना जा रहा है।यह भी गौरतलब है कि बृजभूषण शरण सिंह अपने तीखे तेवरों और समय-समय पर दिए गए बयानों के कारण सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव की खुलकर तारीफ की, तो कभी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर दिए अपने बयानों से सत्तारूढ़ दल को असहज भी किया। महिला पहलवानों के शोषण के आरोप लगने के बाद पिछले लोकसभा चुनाव में उनका टिकट भी काटा गया था, जिसके बाद और उनके बीच दूरियों की खबरें भी सामने आती रही थीं। हालांकि, इन राजनीतिक बयानबाजियों से इतर उनका परिवार पूरी तरह से सत्ताधारी दल के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। उनके बड़े बेटे प्रतीक भूषण सिंह गोंडा सदर से विधायक हैं, जबकि छोटे बेटे करण भूषण सिंह कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं।

परिसीमन पर अखिलेश बोले- भाजपा की बड़ी भूल साबित होगी

लखनऊ(ए)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश में संभावित परिसीमन को लेकर अपना स्पष्ट रुख सामने रखा है। उन्होंने भाजपा की इस कवायद को राजनीति की सबसे बड़ी भूल करार दिया है। अखिलेश यादव ने उन सभी अटकलों का खंडन भी किया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि सपा परिसीमन विधेयक के संसद में पेश होने के दौरान अनुपस्थित रहेगी।



उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी पार्टी का स्टैंड साफ करते हुए लिखा, परिसीमन भाजपा की राजनीति की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा गर्म थी कि लोकसभा और राज्यसभा से समाजवादी पार्टी इस विधेयक पर मतदान के दौरान गैरहाजिर रह सकती है।

ऐसी अटकलों के पीछे तर्क दिया जा रहा था कि यदि सपा, जिसके लोकसभा में 37 सांसद हैं, सदन में अनुपस्थित रहती है, तो केंद्र सरकार को विधेयक पारित कराने के लिए आवश्यक 360 मतों की संख्या अपने आप कम हो सकती है। इससे सरकार के लिए बिल को लोकसभा से पास कराना आसान हो जाता। हालांकि, अखिलेश यादव के बयान ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है।

इसी बीच, केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी है कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से आवश्यक सरकारी कामकाज के लिए लोकसभा को 30 नवंबर को और राज्यसभा को 2 दिसंबर को फिर से बुलाने का अनुरोध किया है। कामकाज की जरूरतों को देखते हुए, दोनों सदनों की बैठक 3 दिसंबर को समाप्त हो सकती है। सरकार के इस कदम के बाद, अखिलेश यादव का परिसीमन पर यह बयान राजनीतिक गलियारों में काफी अहम माना जा रहा है।

12 दिसंबर को पटना में बिहार पुलिस को मिलेगा राष्ट्रपति कलर अवार्ड, गृहमंत्री अमित शाह करेंगे सम्मानित

पटना, (ए)। बिहार पुलिस के इतिहास में 12 दिसंबर का दिन महत्वपूर्ण होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दिन पटना पहुंचकर बिहार पुलिस को देश के सर्वोच्च पुलिस सम्मानों में शामिल राष्ट्रपति कलर अवार्ड से सम्मानित करेंगे। समारोह का आयोजन बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-5 परिसर में किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी समेत पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

सिपाही से डीजीपी तक पहन सकेंगे विशेष बैज

राष्ट्रपति कलर अवार्ड पुलिस संगठन को उसकी उत्कृष्ट सेवाओं, अनुशासन, बीरता और कर्तव्यनिष्ठा के लिए दिया जाता है। इस सम्मान के तहत बिहार पुलिस को विशेष ध्वज और बैज मिलेगा। खास बात यह है कि सिपाही से लेकर डीजीपी तक सभी पुलिसकर्मी अपनी वर्दी पर यह विशेष बैज लगा सकेंगे। यह पूरे पुलिस संगठन की सामूहिक उपलब्धि और गौरव का प्रतीक होगा।

आठ प्लाटून की परेड होगी आकर्षण

समारोह में बिहार पुलिस की आठ प्लाटून परेड में हिस्सा लेंगी। इनमें गोरखा बटालियन, महिला स्वाभिमान बटालियन, स्पेशल टास्क फोर्स (स्त्रञ्ज) और अश्वारोही पुलिस दस्ता शामिल होंगे। परेड के दौरान पुलिसकर्मी अपने अनुशासन और पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन करेंगे। पुलिस बैंड की प्रस्तुति भी कार्यक्रम का हिस्सा होगी।

करीब ढाई घंटे कार्यक्रम में रहेंगे अमित शाह

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह करीब ढाई घंटे तक समारोह में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे परेड की सलामी लेंगे और बिहार पुलिस को राष्ट्रपति कलर अवार्ड प्रदान करेंगे। गौरतलब है कि इसी वर्ष अप्रैल में बिहार पुलिस को राष्ट्रपति कलर अवार्ड देने की घोषणा की गई थी। अब पटना में आयोजित समारोह में यह सम्मान औपचारिक रूप से प्रदान किया जाएगा। इस उपलब्धि के साथ बिहार पुलिस के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा।

संसद के विशेष सत्र पर कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल

नई दिल्ली,(ए)। केंद्र सरकार ने संसद का चार दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की है, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकसभा की बैठक 30 नवंबर और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर से शुरू होगी। कांग्रेस ने सवाल करते हुए कहा है, कि सरकार नियमित शीतकालीन सत्र बुलाने के बजाय विशेष सत्र क्यों बुला रही है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक, जरूरी सरकारी कामकाज पूरा होने के बाद दोनों सदनों की बैठकें 3 दिसंबर को समाप्त हो सकती हैं। हालांकि, सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस दौरान कौन से विधेयक या प्रस्ताव सदन में लाए जाएंगे।

विशेष सत्र को लेकर महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों की चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक, अप्रैल में आगे नहीं बढ़ पाए प्रस्तावों को सरकार दोबारा संसद में ला सकती है। हालांकि, इसकी पुष्टि सरकार की ओर से नहीं की गई है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सवाल उठाया कि सरकार नियमित शीतकालीन सत्र बुलाने के बजाय विशेष सत्र क्यों बुला रही है। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र को नियमित सत्र का विकल्प नहीं बनाया जाना चाहिए और यदि सरकार किसी विधेयक को दोबारा लाना चाहती है तो वह नियमित सत्र में भी ऐसा कर सकती है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी संसद की बैठकें कम होने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद बहस और जवाबदेही का मंच बनने के बजाय केवल विधेयकों पर मुहर लगाने वाली संस्था नहीं होनी चाहिए। थरूर ने संसद का वार्षिक कैलेंडर 9 से 12 महीने पहले जारी करने की मांग की और परिसीमन विधेयक पर व्यापक चर्चा की जरूरत बताई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने महिला आरक्षण को लेकर सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम, 2023 दोनों सदनों से पारित हो चुका है और कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था। उनका सवाल था कि जब महिला आरक्षण का कानून पहले ही पारित है तो नए विधेयक की जरूरत क्यों पड़ रही है और सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर रही। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने भी कहा कि महिला आरक्षण और परिसीमन पर चर्चा करनी है तो यह नियमित शीतकालीन सत्र में की जा सकती है। फिलहाल विशेष सत्र में कौन से प्रस्ताव आएंगे, इसकी तस्वीर सदन की कार्यसूची जारी होने के बाद ही साफ होगी।

भारत की औद्योगिक महत्वाकांक्षा से अमेरिका को क्यों लग रहा डर?

आत्मनिर्भर भारत अब अमेरिकी निशाने पर, टैरिफ लगाने की दे रहा धमकी

नई दिल्ली,(ए)। भारत की महत्वाकांक्षी औद्योगिक रणनीतियां, जैसे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई), अब अमेरिकी प्रशासन के निशाने पर आ गई हैं। अमेरिका ने भारत की वस्तुओं पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है, जिसका आधार यह आरोप है कि भारत घरेलू मांग से कहीं अधिक उत्पादन क्षमता विकसित कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि इससे वैश्विक बाजारों में असंतुलन पैदा हो रहा है और अमेरिकी उद्योगों व रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।



अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ने भारत की औद्योगिक और व्यापार नीतियों की गहन जांच की है। अपनी विस्तृत रिपोर्ट में यूएसटीआर ने भारत की नीतियों को अनुचित बताया है, यह तर्क देते हुए कि सरकारी प्रोत्साहन और हस्तक्षेप के कारण उत्पादन क्षमता घरेलू जरूरतों से कहीं ज्यादा बढ़ रही है। यह संरचनात्मक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता वैश्विक व्यापार के लिए चुनौती पेश कर रही है।

रिपोर्ट में विशेष रूप से मेक इन इंडिया के तहत विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी 25 फीसदी तक बढ़ाने के लक्ष्य पर सवाल उठाए गए हैं, जिसके लिए उत्पादन क्षमता को लगभग दोगुना करना होगा। इसी तरह, पीएलआई योजना के तहत उत्पादन और बिक्री में बढ़ोतरी के आधार पर दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन को भी अमेरिका अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का जनक मानता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता कम करने के प्रयासों को भी अमेरिका वैश्विक व्यापार के लिए चुनौती के रूप में देख रहा है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन द्वारा मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल को भी अमेरिका निर्यात-आधारित उत्पादन बढ़ाने वाला मानता है।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की आपत्तियां केवल इन विशिष्ट योजनाओं तक सीमित नहीं हैं। यूएसटीआर की रिपोर्ट में श्रमिक अधिकारों का कमजोर संरक्षण, विदेशी कंपनियों के लिए बाजार में प्रवेश की बाधाएं और चीन जैसे गैर-बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं से निवेश व आयात के माध्यम से अतिरिक्त वैश्विक उत्पादन को बढ़ावा देना भी चिंता के प्रमुख बिंदु बताए गए हैं। रिपोर्ट में स्टील, सोलर, फार्मास्युटिकल्स, मेडिकल डिवाइस और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) जैसे क्षेत्रों में भारत की बढ़ती उत्पादन क्षमता और सरकारी हस्तक्षेप पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमेरिका का दावा है कि भारत की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता घरेलू मांग से काफी आगे निकल चुकी है।अमेरिका की चिंता का एक बड़ा हिस्सा चीन से भी जुड़ा है। यूएसटीआर का कहना है कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं, खासकर चीन से आने वाले कच्चे माल, निवेश और आपूर्ति शृंखला पर निर्भर है, जिससे भारतीय कंपनियों को कम लागत पर उत्पादन करने का लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में भारत के श्रम कानूनों और श्रमिकों के सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों पर भी सवाल उठाए गए हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक पीरजादा मोहम्मद सईद का निधन

श्रीनगर,(ए)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अनंतनाग से विधायक पीरजादा मोहम्मद सईद का निधन हो गया है। वे 73 साल के थे। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि उनका निधन गुरुवार शाम को हुआ। उनको शुक्रवार को दमहल अचबल, अनंतनाग में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर के सीएमओ ने एक्स पर पोस्ट कर सईद के निधन पर दुख व्यक्त किया।



पोस्ट में लिखा-सीएम उमर अब्दुल्ला ने वरिष्ठ नेता को श्रद्धांजलि देते हुए सार्वजनिक सेवा में उनके लंबे और विशिष्ट करियर और जम्मू-कश्मीर के लोगों के कल्याण में उनके अमूल्य योगदान को याद किया। उन्होंने शोक संतप्त परिवार, दोस्तों और समर्थकों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा को जन्नत (स्वर्ग) में सर्वोच्च स्थान मिलने और परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति मिलने की प्रार्थना की।

जम्मू-कश्मीर सरकार की मंत्री सकीना इटू ने भी एक्स पोस्ट में लिखा-पीरजादा मोहम्मद सईद साहब के निधन से गहरा दुख हुआ। वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अनंतनाग से मौजूदा विधायक थे। उनका कई दशकों तक चला विशिष्ट राजनीतिक करियर था, जिसके दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, विभिन्न सरकारों में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया और विधानसभा में कोकरनाग और अनंतनाग का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने लिखा, सार्वजनिक जीवन में उनका अमूल्य योगदान, लोगों की सेवा के प्रति उनका समर्पण और जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ उनका लंबा जुड़ाव हमेशा बड़े सम्मान के साथ याद किया जाएगा। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार, दोस्तों और समर्थकों के साथ हैं।

जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा रहे पीरजादा ने 2024 के विधानसभा चुनाव में एक और शानदार वापसी की थी, जब उन्होंने अनंतनाग से जीत हासिल की थी। उनका राजनीतिक सफर तीन दशकों तक फैला था। उन्होंने 1987, 2002 और 2008 में विधानसभा में कोकरनाग निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और बाद में जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। कश्मीर विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक, पीरजादा अपने विनम्र व्यवहार, राजनीतिक कौशल और जमीनी स्तर पर गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाते थे। उन्हें पहली बार 2 नवंबर, 2002 को पीडीपी-कांग्रेस गठबंधन सरकार में मंत्री बनाया गया था, जिसका नेतृत्व पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद और बाद में गुलाम नबी आजाद ने किया था।

सपा का जन-मन का मेनिफेस्टो उसकी कथित पीडीए की राजनीति की तरह खोखला

मायावती ने चुनावी घोषणा-पत्र पर निशाना साधते हुए इसे कोरा हवा-हवाई बताया

लखनऊ,(ए)। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी (सपा) द्वारा जारी चुनावी घोषणा-पत्र पर निशाना साधते हुए इसे पीडीए की तरह ही कोरा हवा-हवाई करार दिया है। उन्होंने कहा कि सपा का जन-मन का मेनिफेस्टो उसकी कथित पीडीए की राजनीति की तरह खोखला है और थोथा चना बाजे घना की कहावत को चरितार्थ करता है। मायावती ने सपा पर गरीबों, दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के वास्तविक हितों की अनदेखी करने और धन्नासेठों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। मायावती ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा जन-मन का मेनिफेस्टो के नाम से जारी किया गया उसका प्रण-पत्र पीडीए की तरह ही कोरा हवा-हवाई है तथा थोथा चना बाजे घना की कहावत को ही चरितार्थ करने वाला है। उन्होंने कहा कि जैसे भी इस पार्टी का स्वभाव जगजाहिर तौर पर गरीबों, दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों आदि के वास्तविक हित, कल्याण, मान-सम्मान और सुरक्षा के विरुद्ध अधिकतर संकीर्ण व जातिवादी तथा धन्नासेठ-समर्थक रहा है। इसका एक ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए हाल ही में हुए द्विवार्षिक चुनाव में पीडीए को प्रश्रय देने के बजाय बड़े धन्नासेठ को प्राथमिकता देना है। ऐसी नीतियों और कार्यकलापों से प्रदेश की अपार गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन और पलायन जैसी गंभीर समस्याएं क्या कभी दूर हो पाएंगी? कभी नहीं। मायावती ने कहा कि इन बातों से यह भी साबित होता है कि सपा का जन-मन घोषणापत्र वास्तव में धन-मन वादी अधिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाज के अच्छे लोगों के बजाय पार्टी ऐसे ही धनी और बाहुबलियों को चुनाव मैदान में उतारेगी, जो देश, समाज और जनहित की चिंता कम तथा अपने निजी लाभ और स्वार्थ में ही लगातार डूबे रहते हैं। मायावती ने कहा कि हर हाथ को काम तथा कानून द्वारा कानून का राज विशुद्ध रूप से बसपा की नीति और सिद्धांत हैं, जिस सर्वसमाज और सर्वजन-हितैषी एजेंडे पर बसपा की उत्तर प्रदेश में अब तक रही चारों सरकारों में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अमल करके भी दिखाया गया है।